



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 16 मार्च, 1989/25 फाल्गुन, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यटन विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88-पर्यटन (सचि).—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल (जुगेहड़, मौजा बण्डी) तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पटन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है। अतएव: एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण उप-मण्डल अधिकारी

(नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि पर कब्जा ले सकता है।

भूमि का रेखांक, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

जिला: कांगड़ा :

तहसील:-कांगड़ा:

महाल	खसरा नं०	क्षेत्रफल हकटेयों टेयर में	1	2	3	4	5
1	2	3					
जुगेहड़, मौजा वण्डी	464/3/1	0 07 24	96	0 08 09			
	465/3/1	0 20 32	97	0 07 15			
	467/3/1	0 03 14	8911	0 03 53			
	513/489/1	0 03 99	544199	0 01 98			
	514/489/1	0 09 98	54519911	0 00 75			
	4/1	0 82 77	100	0 02 78			
	4/2	0 01 44	101	0 00 40			
	519/51	4 96 17	102	0 07 67			
	80	0 07 48	10311	0 09 75			
	81	0 06 51	10411	0 10 23			
	82	0 19 52	11411	0 01 92			
	83	0 06 30	546111511	0 01 66			
	84	0 06 08	12011	0 00 49			
	85	0 04 72	12112	0 00 10			
	86	0 05 24	12212	0 02 38			
	87	0 03 71	12412	0 02 13			
	530/90	0 03 45	125	0 19 13			
	531/90/1	0 02 41	126	0 24 46			
	532/91	0 01 20	127	0 05 95			
	533/91/1	0 05 47	128	0 02 08			
	534/92	0 01 60	12811	0 02 38			
	535/92	0 12 61	12812	0 02 20			
	536/92	0 11 40	552112911	0 40 95			
	537/93	0 03 06	552112912	0 34 71			
	538/93	0 03 08	5531129	0 04 74			
	539/93	0 03 04	5541130	0 02 18			
	540/93	0 03 10	5561130	0 01 49			
	541/93	0 03 08	5581130	0 02 94			
	542/95	0 12 62	131	0 02 28			
	543/95	0 10 19	132	0 05 92			
	77	0 06 50	13311	0 09 23			
			13312	0 05 44			
			134	0 05 79			
			135	0 02 64			
			136	0 03 84			

1	2	3	1	2	3
137	0 16 19		159	0 20 82	
138	0 03 93		160	0 10 50	
139	0 02 50		161	0 04 96	
140	0 01 08		163	0 01 35	
141	0 26 24		164	0 01 71	
142	0 03 75		165 1	0 03 58	
143	0 01 45		166	0 00 58	
144	0 06 32		167	0 05 18	
145	0 01 58		169 1	0 03 30	
146	0 03 42		170 1	0 02 62	
147	0 05 50		557 17 1	0 04 22	
148	0 03 94		172 1	0 00 48	
149	0 02 04		173 1	0 01 22	
150	0 03 64		175 2	0 04 75	
151	0 06 61		176 1	0 00 22	
152	0 04 99		177 2	0 00 48	
153	0 02 16		178 2	0 06 39	
154	0 06 79		179 2	0 03 08	
155	0 22 54		214 2	0 02 84	
156	0 00 56				
157	0 01 19	कुल कित्ता ..	107	12 19 13	
158	0 07 83				

शिमला-171002, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88—पर्यटन (सचि):—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल रिच्छयालू मौजा बण्डी, तहसील बजिला कांगड़ा में हवाई पतन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अतिआवश्यक अपक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है। उक्त प्रयोजन के लिये अपक्षित है।

यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि का अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अतिआवश्यक मामला होने के कारण उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व, भूमि पर कब्जा ले सकता है।

भूमि का रेखांक उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरण		1	2	3
जिला: कांगड़ा	तहसील: कांगड़ा	789	0 03 61	
		790	0 01 80	
महाल	खसरा नं०	791	0 00 27	
1	2	79211	0 01 89	
	क्षेत्रफल हैक्टयरो में	79311	0 18 83	
	3	950	0 21 02	
रिच्छालू, मौजा	73812	951	0 07 00	
वण्डी ।	74312	952	0 07 04	
	74411	953	0 16 32	
	75411	954	0 00 46	
	748	955	0 00 23	
	75111	956	0 00 36	
	76011	957	0 00 30	
	76111	958	0 00 64	
	762	960	0 87 08	
	763	961	0 00 76	
	764	962	0 03 92	
	765	963	0 04 68	
	766	96411	0 07 51	
	767	96511	0 14 51	
	768	966	0 00 72	
	769	967	0 00 38	
	770	96811	0 01 08	
	771	97011	0 00 38	
	772	97811	0 00 70	
	773	97911	0 01 15	
	774	98011	0 00 12	
	775	105111	0 01 56	
	776	105211	0 00 50	
	777	105311	0 01 21	
	778	105412	1 33 22	
	779	1055	0 31 13	
	780	1056	0 17 23	
	781	105711	0 14 43	
	782	106011	0 03 98	
	783	106211	0 12 10	
	784	106811	0 02 59	
	786			
	78712			
	788	कुल कित्ता ..	71	8 48 36

शिमला-2, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88-पर्यटन (सचि०)।—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल सनौरा, मौजा दुगियारी, तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पटन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि को अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व, भूमि का कब्जा ले सकता है।

भूमि का रेखांक उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

### विवरणी

जिला : कांगड़ा

तहसील : कांगड़ा:

महाल	खसरा नं०	क्षेत्रफल हेक्टेयरों में	1	2	3
1	2	3			
सनौरा	434/1	0 02 92		450	0 00 15
	435	0 00 52		451	0 00 25
	436	0 00 32		452	0 00 60
	437	0 00 62		453	0 01 47
	438/1	0 00 54		822/454	0 02 49
	439/1	0 00 04		823/454	0 02 43
	440	0 00 80		455/1	0 06 99
	441	0 00 15		456/1	0 08 31
	442	0 02 35		457	0 00 55
	443	0 01 01		458	0 00 35
	444	0 01 88		459	0 00 20
	445	0 02 86		460	0 00 51
	446	0 02 41		461	0 00 66
	447	0 00 66		462	0 00 42
	448	0 00 39		463	0 01 40
	449	0 00 28		464	0 00 50
				465	0 00 66
				469/1	0 00 12
				470/1	0 05 57
				471	0 01 26

1	2	3	1	2	3
472	0 00 30		511	0 01 72	
473	0 01 60		512	0 02 66	
474	0 03 39		513	0 00 40	
475/1	0 03 09		514	0 01 26	
485	0 07 25		515	0 00 09	
488/1	0 16 16		516	0 01 98	
489	0 01 94		517	0 02 88	
490	0 21 16		518	0 03 87	
491	0 00 80		519	0 04 34	
492	0 22 78		520	0 02 85	
493	0 01 32		521	0 02 24	
494	0 10 39		522	0 01 64	
824/495	0 07 73		523	0 04 16	
825/494	0 11 41		524	0 03 79	
496	0 00 48		525	0 01 23	
497	0 00 39		526	0 02 28	
498	0 13 33		528	0 00 42	
499	0 14 77		529	0 41 04	
501	0 01 20		533	0 01 08	
502	0 00 35		558/1	0 00 39	
503	0 00 50		559/1	0 00 06	
504	0 00 16		580/1	0 00 58	
505	0 01 02		583/1	0 00 09	
507	0 01 47		586/1	0 04 21	
508	0 02 06		587/1	0 00 42	
509	0 01 90		584/1	0 00 09	
510	0 01 05		कुल कित्ता..	89	2 86 41

शिमला-2, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88-पर्यटन(सचि०).—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल भेड़ी, मौजा वगडो, तड़पोत व जिना कांगड़ा में हवाई पतन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अतिआवश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा के उपबन्धों के अन्तर्गत इस से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अन्तर्गत उर मण्डल, अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि को अर्जन करने के आदेश लेने का प्रश्न द्वारा निर्देश दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अतिआवश्यक मामला होने के कारण उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि पर कब्जा ले सकता है।

भूमि का रेखांक उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

जिला : कांगड़ा

तहसील : कांगड़ा

महाल	खसरा नं०	क्षेत्रफल हैक्टरों में
भेड़ी, मौजा वण्डी	13/1	0 07 11
	54/1	0 00 42
	55/1	0 10 56
	56/1	0 09 03
	57/1	0 04 22
	66/1	0 01 36
कुल कित्ता ... 6		0 32 70

आदेश द्वारा,  
ए० एन० विद्यार्थी,  
वितायुक्त एवं सचिव।

